

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 45]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 29 जनवरी 2021—माघ 9, शक 1942

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 जनवरी 2021

क्र. F.No. MPSRLM-2021-Rural street vendor-3

यतः सेवाओं या प्रसुविधाओं या सहायकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है, और हितग्राहियों को सुविधाजनक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और यतः पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग ग्रामीण क्षेत्र के पथ विक्रेताओं के लिए मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना, 2020 का संचालन कर रहा है, जिसे ग्राम पंचायतों और जनपद पंचायतों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है;

और यतः योजना के अधीन रूपए 10,000/- ऋण के रूप में निकट के बैंक से ग्रामीण पथ: विक्रेताओं को क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा योजना के दिशा निर्देशों की सीमा के अनुसार दिए जा रहे हैं;

और यतः पूर्वोक्त योजना में मध्यप्रदेश के समेकित निधि से होने वाला आवर्ती व्यय शामिल है;

अतएव, मध्यप्रदेश शासन, आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओंका लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) की धारा 7 के अनुसरण में, एतद् द्वारा, निम्नलिखित अधिसूचित करता है, अर्थात्:-

1. (1) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक पात्र व्यक्ति से एतद् द्वारा अपेक्षा की जाती है कि वह आधार संख्या रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार अधिप्रमाणन कराए।

(2) योजना के अधीन प्रसुविधा लेने के इच्छुक प्रत्येक ऐसा व्यक्ति, जो आधार संख्या नहीं रखता है या जिसने आधार के लिए अभी तक नामांकन नहीं किया है, उसे आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, परन्तु वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के हकदार हैं और ऐसे व्यक्ति किसी भी आधार नामांकन केन्द्र (केन्द्रों की सूची युआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) पर आधार नामांकन के लिए जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12, के अनुसार इसकी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यमसे हितग्राहियों के लिए जो अभी आधार हेतु नामांकित नहीं हुए हैं, उनके आधार नामांकन सुविधाओं की व्यवस्था करना अपेक्षित है और यदि संबंधित ब्लाक या तालुका या तहसील में आधार नामांकन केन्द्र स्थित नहीं हो तो विभाग कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से यूआईडीएआई के विद्यमान रजिस्ट्रार के सहयोग से या स्वतः युआईडीएआई रजिस्ट्रार बनते हुए सुविधाजनक स्थान पर आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराएगा:-

परन्तु योजना के अधीन किसी व्यक्ति को आधार सौंप दिए जाने तक ऐसे व्यक्ति को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत करने की शर्त पर प्रसुविधा दी जाएगी, अर्थात्:-

(क) यदि वह नामांकित हो गया हो, उसकी आधार नामांकन प्रमाणीकरण की पर्ची; और

(ख) निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक, अर्थात्:-

(एक) बैंक या पोस्ट ऑफिस की फोटो पासबुक; या

(दो) स्थायी खाता संख्या (पैन) कार्ड; या

(तीन) पासपोर्ट ; या

(चार) राशन कार्ड; या

(पांच) मतदाता पहचान कार्ड; या

(छह) मनरेगा कार्ड; या

(सात) किसान फोटो पासबुक; या

(आठ) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(नौ) किसी राजपत्रिका अधिकारी या तहसीलदार कार्यालय के अधिकारिक शीर्षपत्र पर जारी किसी ऐसे व्यक्ति का फोटो सहित पहचान प्रमाण पत्र; या

(दस) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज:

परन्तु उपर्युक्त दस्तावेजों को विभाग द्वारा विशिष्ट रूप से पदाभिहित एक अधिकारी द्वारा जांचा जा सकेगा।

2. योजना के अधीन हितग्राहियों को सुविधाजनक रूप से लाभ प्रदान करने के लिए विभाग अपने कार्यान्वयन अभिकरण (एजेंसी) के माध्यम से, यह सुनिश्चित करने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं करेगा और योजना के अधीन आधार की आवश्यकता के प्रति हितग्राहियों को जागरूक बनाने के लिए मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

3. उन सभी मामलों में, जहां आधार अधिप्रमाणन हितग्राहियों के खराब बायोमेट्रिक्स के कारण या किसी अन्य कारण से असफल रहता है, वहां निम्नलिखित क्रियाविधि अपनायी जाएगी, अर्थात्:-

(क) खराब अंगुलीछाप गुणवत्ता के मामले में, अधिप्रमाणन के लिए आईरिस स्केन या चेहरा अधिप्रमाणन सुविधा अपनाई जाएगी, जिससे विभाग अपनी कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से आईरिस स्केन या चेहरा अधिप्रमाणन के साथ अंगुलीछाप अधिप्रमाणन के लिए उपबंध करेगी जिससे निर्बाध रीति से प्रसुविधा प्राप्त हो सके;

(ख) अंगुलीछाप के माध्यम से बायोमेट्रिक्स अधिप्रमाणन या आईआरआईएस या चेहरा अधिप्रमाणन के सफल न होने की दशा में, जहां कहीं साध्य और ग्राह्य हो वहां यथास्थिति सीमित समय वैधता वाले आधार वन टाइम पासवर्ड (ओटीपी) या समय आधारित वन टाइम पासवर्ड द्वारा अधिप्रमाणन प्रदान किया जाएगा;

(ग) अन्य सभी मामलों में जहां बायोमेट्रिक्स या आधार वन टाइम पासवर्ड या टाइम आधारित वन टाइम पासवर्ड अधिप्रमाणन संभव नहीं है, वहां योजना के अधीन प्रसुविधाएं भौतिक आधार पत्र के आधार पर दिए जा सकते हैं, जिनकी अधिप्रमाणिकता आधार पर मुद्रित कोड से त्वरित प्रतिक्रिया (क्यूआर) के माध्यम से सत्यापित की जा सकती है और प्रतिक्रिया कोड रीडर का आवश्यक

- प्रबंध विभाग द्वारा अपनी कार्यान्वयन अभिकरण (एजेंसियों) के माध्यम से सुविधाजनक स्थान पर उपलब्ध कराया जाएगा।
4. यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि योजना के अधीन कोई भी हितग्राही अपनी सम्यक् प्रसुविधाओं से वंचित नहीं है, राज्य सरकार में संबंधित विभाग प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण मिशन (डीबीटी), मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के कार्यालय ज्ञापन डी-26011/04/2017 डीबीटी दिनांक 19 दिसंबर, 2017 में विनिर्दिष्ट अपवाद हैंडलिंग क्रियाविधि का पालन करेगा।
 5. यह अधिसूचना राजपत्र में इस प्रकाशनकी तारीख से प्रवृत्त होगी।

No.F.No. MPSRLM-2021-Rural street vendor-3

S.O.....(E)_ Whereas, the use of Aadhaar as an identity document for delivery of services or benefits or subsidies, the Government delivery processes brings in transparency, efficiency and enables beneficiaries to get their entitlements directly in a convenient and seamless manner by obviating the need to produce multiple documents to prove one's identity;

And whereas, the Panchayat and Rural Development Department, is administering the **Chief Minister Rural Street Vendor Loan Scheme 2020 to Street Vendors of the Rural area**, which is being implemented through the **Gram Panchayats & Janpad Panchayats**;

And whereas, under the Scheme, **Rs. 10,000/- as a loan by nearby bank is given to the Rural Street Vendors**, by the Implementing Agency as per the extant Scheme guidelines;

And whereas, the aforesaid Scheme involves recurring expenditure incurred from the Consolidated Fund of **Madhya Pradesh**;

Now, therefore, in pursuance of section 7 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Government of **Madhya Pradesh** hereby notifies the following, namely:-

1. (1) An individual eligible for receiving the benefits under the Scheme shall hereby be required to furnish proof of possession of the Aadhaar number or undergo Aadhaar authentication.
- (2) Any individual desirous of availing benefits under the Scheme, who does not possess the Aadhaar number or has not yet enrolled for Aadhaar, shall be required to make application for Aadhaar enrolment before registering for the Scheme provided that he is entitled to obtain Aadhaar as per section 3 of the

said Act, and such individuals shall visit any Aadhaar enrolment centre (list available at the Unique Identification Authority of India (UIDAI) website www.uidai.gov.in) to get enrolled for Aadhaar.

(3) As per regulation 12 of the Aadhaar (Enrolment and Update) Regulations, 2016, the Department through its Implementing Agency, is required to offer Aadhaar enrolment facilities for the beneficiaries who are not yet enrolled for Aadhaar and in case there is no Aadhaar enrolment centre located in the respective Block or Taluka or Tehsil, the Department through its Implementing Agency shall provide Aadhaar enrolment facilities at convenient locations in coordination with the existing Registrars of UIDAI or by becoming a UIDAI Registrar themselves:

Provided that till the time Aadhaar is assigned to the individual, benefits under the Scheme shall be given to such individual, subject to the production of the following documents, namely :-

- (a) if he has enrolled, his Aadhaar Enrolment Identification slip; and
- (b) any one of the following documents, namely :-
 - (i) Bank or Post office Passbook with Photo; or
 - (ii) Permanent Account Number (PAN) Card; or
 - (iii) Passport; or
 - (iv) Ration Card; or
 - (v) Voter Identity Card; or
 - (vi) MGNREGA card; or
 - (vii) Kisan Photo passbook; or
 - (viii) Driving license issued by the Licensing Authority under the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988); or
 - (ix) Certificate of identity having photo of such person issued by a Gazetted Officer or a Tehsildar on an official letter head; or
 - (x) any other document as specified by the Department:

Provided further that the above documents may be checked by an officer specifically designated by the Department for the Department.

2. In order to provide benefits to the beneficiaries under the Scheme conveniently, the Department through its Implementing Agency shall make all the required arrangements to ensure that wide publicity through the media shall be given to the beneficiaries to make them aware of the said requirement.

3. In all cases, where Aadhaar authentication fails due to poor biometrics of the beneficiaries or due to any other reason, the following remedial mechanisms shall be adopted, namely:-

- (a) in case of poor fingerprint quality, iris scan or face authentication facility shall be adopted for authentication, thereby the Department through its Implementing Agency shall make provisions for iris scanners or face authentication along with finger-print authentication for delivery of benefits in seamless manner;
- (b) in case the biometric authentication through fingerprints or iris scan or face authentication is not successful, wherever feasible and admissible authentication by Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (OTP) with limited time validity, as the case may be, shall be offered,
- (c) in all other cases where biometric or Aadhaar One Time Password (OTP) or Time-based One-Time Password (OTP) authentication is not possible, benefits under the Scheme may be given on the basis of physical Aadhaar letter whose authenticity can be verified through the Quick Response code printed on the Aadhaar letter and the necessary arrangement of Quick Response code reader shall be provided at the convenient locations by the Department through its Implementing Agency.

4. in order to ensure that no bona fide beneficiary under the Scheme is deprived of his due benefits, the concerned Department in the state Government and Union Territory Administration shall follow the exception handling mechanism as specified in the Office Memorandum of Direct Benefit Transfer Mission, Cabinet Secretariat, Government of India no. D-26011/04/2017-DBT dated 19th December 2017.

5. This notification shall come into effect from the date of its publication in the Official Gazette.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शोभा निकुम, अवर सचिव.